पोलैंड के काटोवाइस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- टी. जयरमण (प्रोफेसर, स्कूल ऑफ हैबिटैट स्टडीज)

15 जनवरी, 2019

पोलैंड के काटोवाइस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के दलों (सीओपी -24) का 24 वां सम्मेलन विकासशील देशों के लिए जलवायु के मोर्चे पर बहुत कम उत्साह जनक रहा है। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए तथाकथित 'नियम पुस्तिका' के पारित होने के साथ, विकसित देशों ने बड़े पैमाने पर एक वैश्विक जलवायु शासन स्थापित करने में सफलता हासिल की है, जो उन्हें रणनीतिक लाभ देता है और उनकी कुछ प्रमुख चिंताओं को स्वीकार करता है। यह एक नई, विरोधाभासी स्थिति बनाने का संकेत देता है, जहां शासन का दायरा और जटिलता मौलिक रूप से बहुउद्देशीय है, जिसके लिए शासन का निर्माण किया गया है।

भेदभाव का दौर

इस रणनीतिक सफलता के दिल में जलवायु कार्रवाई में वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच भेदभाव का पर्याप्त माहौल बना हुआ है। इस प्रक्रिया का पहला चरण पेरिस समझौते के साथ शुरू हुआ, जब विकसित राष्ट्रों को अपनी प्रतिबद्धता के सापेक्ष पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी बेंचमार्क के बिना, विकासशील देशों के साथ, जलवायु शमन पर स्वैच्छिक प्रतिबद्धता बनाने की अनुमति दी थी। काटोवाइस में यह प्रक्रिया सभी देशों के लिए रिपोर्टिंग, निगरानी और मूल्यांकन के समान मानकों के साथ आगे बढ़ी। सतही रूप से प्रभावशाली होते हुए, रिपोर्टिंग की आवश्यकता वास्तविक दिखाई देती है, जब हमें पता चलता है कि उनकी एकरूपता में वे मालदीव के लिए उतने ही अभिप्राय रखते हैं जितने कि अमेरिका के लिए। इस एकरूपता का वास्तविक लक्ष्य निश्चित रूप से सबसे गरीब राष्ट्र नहीं हैं, जिन्हें छूट प्रदान की गई है, बल्कि बड़े विकासशील राष्ट्र भी हैं। सभी विकासशील राष्ट्रों को इन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में अस्थिरता से लचीलापन प्रदान किया गया है, रियायत को कई शर्तों के साथ कम क्रम में पूर्ण अनुपालन के लिए मजबूर करने के इरादे से बचाव किया गया है।

रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भी कठोरता के लिए छद्म वैज्ञानिक चिंता द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो स्वयं जलवायु विज्ञान की सटीकता से अधिक है। दरअसल, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ग्लोबल वार्मिंग पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की हालिया विशेष रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया का वैश्विक कार्बन बजट समाप्त होने से पहले अभी भी संचयी वैश्विक उत्सर्जन की मात्रा में पर्याप्त अनिश्चितता है। इस तरह की अनिश्चितता के सामने, 500 किलो टन या 0.05% राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रति देश में रिपोर्टिंग की आवश्यकता का वैज्ञानिक महत्व बहुत कम है। प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त की जा रही रिपोर्ट में कठोरता अधिक समान है। प्राथमिक गणित हमें सूचित करता है कि एक छोटे उत्सर्जक के उत्सर्जन के बड़े प्रतिशत की तुलना में एक बड़े उत्सर्जक के उत्सर्जन का एक छोटा प्रतिशत निरपेक्ष रूप से बड़ी मात्रा में होगा।

लेकिन समस्या का मूल कारण इन सार्वभौमिक नियमों की गंभीर प्रकृति और जलवायु शमन में अग्रणी देशों द्वारा पहल की कुल कमी के बीच विरोधाभास से संबंधित है। सभी विकसित देश प्रत्यक्ष उत्पादन या आयात के माध्यम से जीवाश्म ईंधन में निवेश कर रहे हैं। जिनमें से कई घरेलू राजनीतिक दबावों के कारण परमाणु ऊर्जा के गिरावट के कारण ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ओईसीडी देशों के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।

इस घटना में, COP-24 पर विवाद छिड़ गया कि क्या IPCC की विशेष रिपोर्ट का स्वागत किया जाना चाहिए या केवल इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह बस भ्रमित करने वाला है। पूर्व पसंद के लिए कम से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील देशों की मुखर दलीलों के बावजूद, पर्याप्त कार्रवाई की अनुपस्थिति में, ऐसे प्रतीकात्मक इशारे स्पष्ट रूप से कम असरदार होते हैं। वास्तव में, रिपोर्ट में ही प्रतीत होता है कि विकसित देशों द्वारा अधिक से अधिक शमन करने के तरीके को इंगित करने के बजाय 'नियम पुस्तिका' के अनुमोदन में विकासशील देशों को केवल मोहर लगाने के लिए उपयोग किया गया है।

उदाहरण के लिए, विशेष रिपोर्ट ने विकसित देशों को जलवायु वित्त की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ इसके वितरण में तेजी लाने के लिए बहुत कम प्रेरित किया है। विकासशील दुनिया द्वारा लंबे समय से तर्क दिया जा रहा है कि जलवायु वित्त का भंडार सार्वजनिक स्रोतों से भरा जाना चाहिए। इसके विपरीत, विकसित देशों ने वित्त सहायता के अन्य स्रोतों को शामिल करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें एफडीआई और इक्विटी प्रवाह शामिल हैं, जो जलवायु सहायता के प्रवाह के लेखांकन में सम्मिलित हैं, और यह विकासशील देशों की

जरूरत है। नियम पुस्तिका के अनुसार, निजी क्षेत्र का प्रवाह या ऋण, जो विकासशील देशों की ऋणग्रस्तता को बढ़ाएगा, को यूएनएफसीसीसी के तहत विकसित देश के दायित्वों की पर्याप्त पूर्ति माना जाएगा।

भारत, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय में निष्पक्षता की आवश्यकता की अपनी अभिव्यक्ति के बावजूद, 'नियम पुस्तिका' के कई पहलुओं में इन धारणाओं के संचालन को प्राप्त करने में विफल रहा है। भले ही भारत ने निष्पक्षता के लिए जोर दिया हो, विशेष रूप से पेरिस समझौते की आवधिक समीक्षा के लिए बेंचमार्क में, लेकिन यह अपनी बात रखने में विफल रहा है। इसके विपरीत, ब्राजील ने कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित मामलों पर अपना आधार रखा और इस मामले को अगले साल के शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम रूप देने के बारे में चिंतित था।

आवश्यकताओं की खराब अभिव्यक्ति

नई दिल्ली ने यह रेखांकित किया कि काटोवाइस में क्या दांव पर था और परिणाम भविष्य में भारत के विकासात्मक विकल्पों की एक गंभीर संकीर्णता को दर्शाता है। कई पर्यावरण और जलवायु थिंक टैंक, एनजीओ और आंदोलनों ने भी वार्ता में सरकार के पक्ष को कमजोर करने में अपना योगदान दिया है। जलवायु के विषय पर विकसित राष्ट्रों के पक्ष को बिना विरोध मान लिया गया, जहाँ वे नैतिक आधार पर घरेलू कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, जबकि तथ्य यह है कि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक सामूहिक समस्या है। COP-24 में भारतीयों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी भारत की जरूरतों की व्यापक अभिव्यक्ति पिछले कई वर्षों में सबसे कम देखी गयी है।

COP-24 के अंतिम भाग में, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के समूह ने 'नियम पुस्तिका' के अंतिम रूप में निष्पक्षता और जलवायु न्याय की उपेक्षा पर भारत के आरक्षण की मांग की, जबकि व्यापक G-77 प्लस चीन गठबंधन ने असंतुलित प्रकृति पर खेद व्यक्त किया। लेकिन 'रूलबुक' के बावजूद, इसे अपनाया गया, COP-24 एक वैश्विक जलवायु शासन को संकेत देता है, जो केवल वैश्विक अमीरों के हितों और लाभों की रक्षा करता है और एक बड़े हिस्से के विकासात्मक भविष्य को अधर में छोड़ दिया है।

GS World टीम...

COP -24

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पोलैंड के काटोवाइस नगर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचे (UNFCCC) से सम्बंधित पक्षकारों का 24वाँ सम्मलेन COP-24 सम्पन्न हुआ।
- इस सम्मलेन में एक भारतीय पैविलियन भी लगाया गया, जिसके उद्घाटन में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सम्मिलित हुए।
- भारतीय पैविलियन की थीम थी-"एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड/"One World One Sun One Grid"।
- वैश्विक जलवायु से सम्बंधित कार्यकलाप के लिए भारत के नेतृत्व को विश्व सराहता है।
- इसी क्रम में इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी को "चैंपियन ऑफ दी अर्थ पुरस्कार" दिया था।
- यह पुरस्कार उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ को आगे बढ़ाने तथा भारत को 2022 तक प्लास्टिक-मुक्त करने के उनके संकल्प के लिए दिया गया था।

COP-24 क्या है?

- COP-24 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचे (UNFCCC) से सम्बंधित पक्षकारों के सम्मेलन को कहते हैं।
- यह संस्था UNFCCC के प्रावधानों के कार्यान्वयन और उसकी समीक्षा सुनिश्चित करती है।

UNFCCC क्या है?

- UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विषयक संधि है, जो 21 मार्च, 1994 से लागू है। अब इसमें विश्व के लगभग सभी देश सदस्य बन चुके हैं।
- दिसम्बर, 2015 तक इसमें 197 सदस्य हो गये थे।
- इस संधि का उद्देश्य जलवायु प्रणाली में मानव के खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना है।

जलवायु परिवर्तन हेतु 200 बिलियन डॉलर का निवेश

सन्दर्भ

- हाल ही में विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।
- विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021-25 के लिए जलवायु परिवर्तन की मुसीबत से निपटने के लिए फंडिंग को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है।
- विश्व बैंक द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर करने की घोषणा की गई है।
- विश्व बैंक ने राशि दोगुनी करने की घोषणा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के समिट में की थी।
- विश्व बैंक द्वारा जारी बयान में कहा गया कि लगभग 100 अरब डॉलर सीधे विश्व बैंक से फंड किए जाएंगे।
- इसके अलावा शेष राशि को विश्व बैंक की दो एजेंसियों से जुटाया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों ने विकासशील देशों में निवेश करने पर सहमति जताई थी।
- वर्ष 2020 तक के लिए 100 बिलियन डॉलर दिए जाने हैं। वर्ष 2016 में 48.5 बिलियन डॉलर और 2017 में 56.7 बिलियन डॉलर दिए गए थे।
- 200 में से 100 बिलियन डॉलर की रकम विश्व बैंक की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा बाकी पैसा वर्ल्ड बैंक की जुड़ी एजेंसियों से जुटाया जाएगा।
- विश्व बैंक के सीनियर डायरेक्टर जॉन रूमे के अनुसार यदि हम उत्सर्जन कम करने में नाकाम रहते हैं, तो 2030 तक 10 करोड़ लोग गरीबी में पहुंच जाएंगे।
- अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका से 13 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं।
- विकासशील देशों के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों तक मदद पहुंचती रहे, इसके लिए विश्व बैंक एक ढांचा बनाना चाहता है।
- विश्व बैंक स्मार्ट खेती और पानी की उपलब्धता के लिए निवेश करेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉप-24 सम्मेलन का आयोजन पोलैण्ड के काटोवाइस में किया गया।
2. कॉप-24 सम्मेलन में एक भारतीय पैविलियन लगाया गया, जिसकी थीम 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड'' थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. यू.एन.एफ.सी.सी.सी. (UNFCCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विषयक संधि है, जिसे 1994 से लागू किया गया।
2. इस संधि का उद्देश्य जलवायु प्रणाली में मानव के खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. COP-24 related to climate change has been organized in Katowice, Poland.
2. A pavallion has been setup in COP-24 conference, the theme of which was "One World, One Sun, One Grid".

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements regarding UNFCCC-

1. It is an international treaty related to environment, which was implemented in 1994.
2. The objective of this treaty is to restrict the dangerous human intervention in climate system.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में सम्पन्न पोलैंड के काटोवाइस शहर में जलवायु परिवर्तन संबंधी कॉप-24 सम्मेलन विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को तरजीह देता है। यह भारत के संदर्भ में विकासात्मक विकल्पों की एक गंभीर संकीर्णता को किस प्रकार दर्शाता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Recently concluded COP-24 in Katowice city of Poland related to climate change gives importance to the developed nation over developing nation. How this shows the serious narroness of developmental options for India? Discuss. (250 Words)

नोट : 14 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।